



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 नवम्बर, 2000/27 कार्तिक, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला, 31 अक्तूबर, 2000

संख्या जी० ए० डी०-सी० (पी० ए०) 4-1/95-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) की धारा 8 और 9 के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम विनियमित करने हेतु, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम, नियम, 2000 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि विषय या मन्दर्भ में विरुद्ध न हों.—

- (क) "अधिनियम" मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 अभिप्रेत है;
- (ख) "सम्प्रीक्षा अधिकारी" से महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,
- (घ) "मन्जुरी प्राधिकारी" से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अभिप्रेत है; और
- (ङ) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

मोटर कार अग्रिम

3. अग्रिम जब अनुज्ञेय होगा.—मन्त्री को मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, संदत्त किया जा सकेगा ताकि वह अपने कार्यालय के कर्त्तव्यों का सुविधापूर्वक तथा दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

4. अग्रिम की अधिकतम रकम.—आश्रित मोटर कार के क्रय हेतु अधिकतम रकम, जो मन्त्री को अग्रिम के रूप में दी जा सकेगी, 10 लाख रुपए या खरीदी जाने वाली मोटर कार की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि मन्त्री ने इन नियमों के नियम 13 के अधीन या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1982 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया है तो मोटर कार अग्रिम की कुल रकम की परिसीमा मन्त्री द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां मन्त्री ने, यथा स्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या विधान सभा सदस्य की हैसियत में मोटर कार अग्रिम ले रखा हो की हैसियत में मोटर कार अग्रिम ले रखा हो तो मोटर कार की कुल रकम की परिसीमा उसे पहले दिए गए मोटर कार अग्रिम सहित दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

5. अग्रिम की वसूली.—(1) इन नियमों के नियम 4 के अधीन मन्जूर अग्रिम की वसूली उस पर ब्याज सहित 180 सप्ताह मासिक किस्तों में की जाएगी। शेष पदावधि को ध्यान में रखते हुए या यदि मन्त्री स्वयं ऐसा चाहे तो सरकार कम संख्या की किस्तों में वसूली के आदेश कर सकेगी। कटौती, अग्रिम न लेने के पश्चात् लिए जाने वाले प्रथम वेतन से आरम्भ की जाएगी।

(2) 3-12-1993 को या उसके पश्चात् स्वीकृत ऋण की बाबत 5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित होगा :

परन्तु 3-12-1993 से पूर्व स्वीकृत ऋण पर नियत ब्याज की दर, अग्रिम के पूरे समय तक वही लागू रहेगी।

(3) यदि कोई मन्त्री किसी कारणवश अग्रिम का पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही किसी कारणवश मन्त्री पद पर नहीं रहता है किन्तु विधान सभा का सदस्य बना रहता है तो मासिक किस्तें उसे विधान सभा सदस्य के रूप में अनुज्ञेय विभिन्न भत्तों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूल की जाएगी।

(4) यदि कोई मन्त्री अग्रिम के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं रहता है परन्तु पेंशन का हकदार है तो उसे मिलने वाली पेंशन में विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूली हो जाएगी तथा शेष रकम उसके द्वारा मासिक किस्तों के नियमित रूप से सरकारी कोष में जमा की जाएगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वह चलायन की एक प्रति सरकार के नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि वह विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तथा पेंशन को लेने के हकदार नहीं है तो उसके द्वारा मासिक किस्तें, उस पर प्रोद्भूत व्याज सहित नियमित रूप से प्रतिमास सरकार को जमा की जाएगी तथा इसके संदाय के प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) अग्रिम तथा उस पर प्रोद्भूत व्याज की वसूली से पूर्व ही मृत्यु होने की दशा में मन्त्री या विधान सभा सदस्य के विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों द्वारा अग्रिम पर प्रोद्भूत व्याज सहित अग्रिम की शेष रकम एक मुश्त सरकारी कोष में जमा करवाई जाएगी, और वह समस्त रकम के जमा किए जाने के प्रमाण में चालान की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत करेगा/करेंगे।

(7) यदि यथास्थिति, मन्त्री या उसका विधिक प्रतिनिधि अग्रिम के मूल या उस पर व्याज की मासिक किस्तों की नियमित अदायगी नहीं करता है या यदि वहां वे दिवालिया हो जाता/जाते हैं या ऋण की अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन या पालन करने में विफल रहता है/रहते हैं तो इस दशा में ऋण की सम्पूर्ण मूल रकम या उसमें से जितना कि उस समय देय तथा अमंदात रहा हो, सरकार को उस पर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर से व्याज सहित एक मुश्त में तत्काल देय होगा। सरकार का उप-युक्त बकाया रकम को "भू-राजस्व के बकाया" के रूप में वसूल करने की स्वतन्त्रता होगी। विधान सभा सचिवालय द्वारा इस प्रभाव में की गई वसूली उपर्युक्त शर्तों पर विचार करते हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार के क्रय के लिए ऋण अग्रिम) नियम, 1979-ए, जैसे समय-समय पर प्रवृत्त हो, के अधीन विनियमित की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—प्रतिमास वसूल की जाने वाले अग्रिम की रकम अतिन्म किस्त, जिसमें शेष रकम रुपये के किसी अंश सहित वसूल की जानी है, को छोड़कर पूरे रुपये में निश्चित की जाएगी।

6. मोटर कार का विक्रय.—(1) मन्त्री के पद त्याग देने के सिवाय, अग्रिम की सहायता से खरीदी गई मोटर कार को बेचने के लिए, मन्त्री द्वारा सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाएगी, यदि ऐसे अग्रिम का उस पर प्रोद्भूत व्याज सहित पूर्णतः प्रति संदाय नहीं किया गया हो। यदि मन्त्री मोटर कार और उसके दायित्व को किसी अन्य मन्त्री को अन्तरित करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की ऐसी घोषणा के देने के अध्याधीन कि उसे जानकारी है कि उसे अन्तरित की गई मोटर कार सरकार के पाम बंधक के अध्याधीन रहेगी और यह कि कार को अन्तरित करने वाले मन्त्री द्वारा निष्पादित बंधक पत्र के निबन्धनों और उपबन्धनों को नियम 8 के अधीन आवद्ध कर होगा। सरकार के आदेशों से अनुमति दी जा सकेगी।

(2) ऐसे भी मामलों में जहां मोटर कार का अग्रिम को उस पर व्याज सहित पूर्णतः प्रतिसंदाय से पहले ही विक्रय कर दिया जाता है वहां विक्रय के अग्रिम, जहां तक आवश्यक हो ऐसे बकाया अतिशेष के प्रतिसंदाय के लिए ही उपयोजित किए जाएं।

परन्तु यह कि जब मोटर कार या इसलिए विक्रय किया गया हो कि अन्य मोटर कार खरीदी जा सकेगी, सरकार मन्त्री को निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन ऐसे विक्रय हेतु विक्रय के आग्रामी को प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी, अर्थात् :—

(क) बकाया रकम को नई कार की लागत से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं ;

(ख) बकाया रकम का प्रतिसंदाय पूर्व नियत दर से जारी रहेगा; और

(ग) नई कार सरकार के पास बन्धक और बीमाकृत होगा।

7. अवधि जिसके भीतर कार खरीदने के लिए वार्तापूर्ण की जा सकेगी—मन्त्री जो मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम लेता है खरीदने के लिए वार्ता पूर्ण करेगा और अग्रिम लेने की तारीख से एक महीने के भीतर मोटर कार के लिए पूर्ण अदायगी करेगा ऐसी सम्पूर्ति और अदायगी के न होने पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि उस पर एक महीने के ब्याज सहित सरकार को वापिस की जाएगी। व्यक्तिगत की दशा में सरकार द्वारा व्यवहार की सम्पूर्ति के लिए फिर भी एक महीने की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। जब मोटर कार पहल ही खरीदी गई हो और पूरा सदा कर दिया हो अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होगा। उस दशा में जिसमें अदायगी भागतः की हो तो अग्रिम की राशि बकाया तक ही सीमित होगी जैसा मन्त्री द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

8. करार का निष्पादन—अग्रिम लेते समय मन्त्री प्ररूप-1 में करार निष्पादित करेगा और खरीद पूर्ण होने पर जिसमें वह अग्रिम के लिए सरकार को प्रतिभूति के रूप में मोटर कार को आड़मान करते हुए, प्ररूप-II में बन्धक-पत्र निष्पादित भी करेगा। मोटर कार की लागत कीमत बन्धक-पत्र के साथ संलग्न प्रतिसूचि के विनिर्देशों में दर्ज की जाएगी।

टिप्पणी:—करार प्राप्ति सादे कागज पर निष्पादित किए जाएंगे और लिखित पर स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्री-करण प्रभार यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

9. संपरीक्षा अधिकारी को प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना—जब अग्रिम लिया जाता है, मंजूरी प्राधिकारी संपरीक्षा अधिकारी को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि अग्रिम लेने वाले मन्त्री न प्ररूप-II में करार को हस्ताक्षरित कर लिया है। और यह सही है। मंजूरी प्राधिकारी देखेगा कि मोटर कार अग्रिम लेने की तारीख से एक महीने के भीतर या ऐसी अवधि में जेसे नियम 7 के अधीन कार्रवाई सम्पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा वैयक्तिक मामलों में विनिर्दिष्टया अनुज्ञात की जा सकेगी खरीद की गई है और प्रत्येक बन्धक पत्र को तत्परता से संपरीक्षा अधिकारी को अन्तिम अभिलेख से पूर्व परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

10. बन्धक-पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा और उसका रद्द करना—बन्धक-पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा जब अग्रिम का उस पर ब्याज सहित पूर्णरूप में प्रतिसंदाय कर दिया जाता है बन्धन-पत्र संपरीक्षा अधिकारी से अग्रिम और ब्याज के सम्पूर्ण प्रतिसंदाय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके सम्यक् रूप से रद्द करके सम्बद्ध मन्त्री को वापिस किया जाएगा।

11. मोटर कार का शोना.—अग्रिम से खरीदी गई मोटर कार का अग्नि, चोरी या दुर्घटना द्वारा पूर्ण हानि के विरुद्ध किसी माधारण बीमा कारखार करने वाली कम्पनी/बीमा नियम के साथ बीमा किया जाएगा शोना शर्तियों में प्ररूप III के अनुसार खंड होगा जिसमें नियम स्वामी की अपक्षा, सरकार को मोटर कार को हुई हानि या क्षति, जिसकी प्रतिपूर्ति, मुरम्मत, यथा पूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है देने का करार करती हैं। ऐसी क्रय की तारीख के एक महीने के भीतर प्रभावी होगा।

भवन निर्माण अग्रिम

12 अग्रिम जब अनुज्ञेय होगा—प्ररूप -IV पर दिए गए आदेशन पर, मन्त्री को उसके समुचित रहन-सहन के लिए अपना भवन निर्माण करने अथवा निर्मित भवन को खरीदने के लिए प्रतिदेय अग्रिम संदत्त किया जाएगा।

13. अग्रिम की अधिकतम रकम.—मन्त्री को भवन निर्माण या निर्मित भवन का क्रय करने के लिए अग्रिम की अधिकतम रकम दस लाख रुपये या वास्तविक कीमत या भवन निर्माण की लागत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि मन्त्री ने इन नियमों के नियम 4 क अधीन या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार अग्रिम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम ले रखा हो तो भवन निर्माण अग्रिम की कुल रकम की परिसीमा मन्त्री द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहाँ मन्त्री ने, यथा स्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की हैमियत से गृह निर्माण अग्रिम लिया है तो उसे पूर्व में दिए गए गृह निर्माण अग्रिम सहित गृह निर्माण की कुल रकम दस लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी ।

14. मंदाय का ढ़ंग—इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय 3 अग्रिम की रकम का भुगतान निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :—

(1) अपने भवन के निर्माण के लिए—

- (क) प्रथम किस्त, निर्माण प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृत अग्रिम के 50 प्रतिशत के बराबर; और
- (ख) द्वितीय तथा अन्तिम किस्त, भवन की छत की संहतक पूर्ण होने पर, कुल अग्रिम का अतिशेष 50 प्रतिशत ।

(2) नव निर्मित भवन का क्रय करने एक मुश्त दिया जाएगा ।

टिप्पणी—मन्त्री, यह प्रमाणित करते हुए, एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम का प्रयोग उसके द्वारा उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह रकम उसे अग्रिम के रूप में दी गई है, जिसे उस द्वारा उपयुक्त प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप से प्रयुक्त करने के लिए पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा ।

15. अग्रिम की वसूली.—(1) इन नियम के नियम 13 के अधीन स्वीकृत अग्रिम तथा उस पर प्रोदभूत होने वाले व्याज की वसूली 180 समान मासिक किस्तों में की जाएगी । सरकार मन्त्री की शेष पदावधि को ध्यान में रखते हुए या यदि मन्त्री स्वयं ऐसा चाहे तो कम, संख्या की किस्तों में वसूली के आदेश दे सकती । कदाचित्, प्रथम किस्त प्रत्येक एक मुश्त अग्रिम लेने के पश्चात् लिए जाने वाले प्रथम वेतन से आरम्भ की जाएगी ।

(2) 3-12-1993 को या पश्चात् स्वीकृत ऋण की वावत 5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण व्याज प्रभारित होगा :

परन्तु 3-12-1993 से पूर्व स्वीकृत अग्रिम पर नियत व्याज की दर अग्रिम के पूरे समय तक वही लागू रहेगी ।

(3) यदि कोई मन्त्री अग्रिम का पूर्ण प्रतिभंदाय होने से पूर्व ही किसी कारणवश मन्त्री पद पर नहीं रहता है किन्तु विधान सभा का सदस्य बना रहता है तो मासिक किस्तें उसे विधान सभा सदस्य के रूप में अनुज्ञेय विभिन्न बातों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूल की जाएगी ।

(4) यदि कोई मन्त्री किसी कारण वश अग्रिम-के पूर्ण प्रतिसंदाय होने के पूर्व ही किसी कारणवश मन्त्री पद पर नहीं रहता है किन्तु पेंशन का हकदार है, तो उसे मिलने वाली पेंशन में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूली की जाएगी तथा मासिक किस्तों की बकाया रकम उसके द्वारा नियमित रूप से खजाने में जमा की जाएगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वह चालान की एक प्रति सरकार के नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि वह विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तथा पेंशन का हकदार भी नहीं बनता है तो उसके द्वारा मासिक किस्तें उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित नियमित रूप में सरकारी खजाने में जमा करनी पड़ेगी तथा इसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को प्रत्येक माह प्रस्तुत करनी पड़ेगी।

(6) अग्रिम तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली से पूर्व ही मृत्यु की दशा में मन्त्री अथवा विधान सभा सदस्य के विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों द्वारा मासिक किस्त नियमित रूप में सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी जिसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को प्रत्येक माह प्रस्तुत करनी पड़ेगी।

(7) यदि यथास्थिति मन्त्री या उसका विधिक प्रतिनिधि मूल धनराशि अथवा उस पर ब्याज की मासिक किस्त की नियमित अदायगी नहीं करता या यदि वह दिवालिया हो जाता है या ऋण के अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन या पालन करने में विफल होता है तो इस दशा में ऋण की सम्पूर्ण मूल रकम या उसमें से इतना जितना कि उस समय देय तथा असंदात रहा हो सरकार को उस पर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज सहित एक मुश्त में तत्काल देय होगी। सरकार को उपर्युक्त बकाया राशि "भू-राजस्व के बकाया" के रूप में वसूल करने की स्वतन्त्रता होगी।

स्पष्टीकरण.—मासिक रूप में वसूल की जाने वाली अग्रिम धनराशि अन्तिम किस्त जिसमें शेष राशि रुपये के किसी अंग सहित वसूल की जानी है को छोड़कर पूरे रुपये में नियत की जाएगी।

16. ऋण के भुगतान की सुरक्षा हेतु बंधक-पत्र निष्पादन का दायित्व.—किसी मन्त्री का यदि अग्रिम राशि तथा प्रोद्भूत ब्याज का पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही निधन हो जाता है अथवा वह मन्त्री पद पर नहीं रहता है तो इसके कनस्वरूप सरकार को होने वाली हानि की प्रतिभूत करने के लिए उस भवन को जो निमित्त किया गया है अथवा खरीदा गया है को उस भूमि सहित जिस पर वह भवन है, को प्रह्व V पर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास बंधक किया जायेगा जिसका निष्पादन यथास्थिति पहली किस्त अथवा एक मुश्त राशि के भुगतान से पूर्व किया जायेगा तथा देय राशि की पूरी अदायगी के पश्चात् बंधक को प्रह्व-VI पर प्रतिहस्तांतरण विवेक के निष्पादन पर मुक्त किया जायेगा बंधक-पत्र के निष्पादन होने पर, मंजूरी प्राधिकारी उस भूमि पर जिस पर उक्त भवन खड़ा है या उसे निमित्त करने का प्रस्ताव है, आवेदक के हक को शुद्धता से अपने आप को संतुष्ट करेगा।

17. परिसर को अच्छी अवस्था में रखने तथा आग में जोखिम आदि के लिए बीमा कराने का दायित्व.—मन्त्री अपने खर्च पर भवन को अच्छी अवस्था में रखेंगे तथा उसे सभी ऋण भारों से भी मुक्त रखेंगे। वह इसका आग, बाढ़ आदि-आदि के लिए इतनी राशि तक का बीमा करवाएंगे जो कि स्वीकृत अग्रिम धनराशि से कम कान हो तथा इस प्रयोजन का वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

18. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971, हिमाचल प्रदेश उप-मन्त्रियों (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971, हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों (भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 1981 और हिमाचल प्रदेश उप-मन्त्रियों (भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 1982 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरस्तन के हवा हए पो उतपुक्त उा नियम (1) के अधीन निरस्तन नियमों के अधीन की गई कोई बात, या कार्रवाई इन नियमों के प्रथम विधिमार्ग्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

प्ररूप-1

मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम लत समय निष्पादित किए जान वाले करार का प्ररूप
(नियम 8 देखें)

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री..... मन्त्री, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें आगे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वरिष्ठ प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिनी भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "सरकार हिमाचल प्रदेश" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिनी भी है) के बीच आज तारीख..... को किया गया है ।

उधार लेने वाले ने हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के अधीन मोटर कार खरीदने के लिए सरकार को रु0 (..... रुपये) के ऋण के लिए आवेदन किया है और सरकार इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट निबन्धनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को उधार देने के लिए सहमत हो गई है ।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उधार लेने वाले को..... रु0(..... रुपये) की संदत्त राशि के प्रतिफल में पक्षकारों के बीच करार किया जाता है (उधार लेने वाला जिनकी पावती की अभिस्वीकृति करता है) उधार लेने वाला सरकार के साथ करार करता है कि :-

(1) जैसा उक्त नियम द्वारा उपबन्धित है उसे विधान सभा सदस्य के रूप में संदेय वेतन या भत्ते पेंशन से 180 मासिक कटौतियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज सहित कथित राशि को सरकार को संदत्त करेगा । (जितनी अधिक वसूल की जा सके और शेष उसके द्वारा नकद सरकारी कोष में जमा की जाएगी और सरकार को ऐसी कटौतियां करने की प्राधिकृत करता है यदि उधार लेने वाला पेंशन लेने का हकदार न हो तो प्रोद्भूत ब्याज सहित मासिक किस्त उसके द्वारा नियमित रूप से सरकारी कोष में जमा की जाएगी तथा वह सरकार को उक्त नियमों में यथा उपबन्धित जमा की गई राशि के साक्ष्य स्वरूप चलान की प्रति प्रस्तुत करेगा) ।

(2) मोटर कार की खरीद में उक्त ऋण की पूर्ण राशि को व्यय यदि संदत्त वास्तविक कीमत ऋण से कम हो तो उनके अन्तर का प्रतिभंदाय सरकार को इन बिलेखों की तारीख से एक मास के भीतर तत्काल करेगा ; और

(3) उधार लेने वाले को यथा पूर्वोक्त उधार दी गई राशि के लिए सरकार के पास प्रतिपूर्ति के रूप में उक्त मोटर कार के आड़मान करने वाले दस्तावेजों और उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित प्ररूप में ब्याज का निष्पादन करेगा ।

इसके द्वारा अन्त में यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि इन बिलेखों की तारीख से एक महीने के भीतर या बढ़ाई गई अवधि के भीतर पूर्ववत् रूप में मोटर कार को और आड़मान नहीं

की जाती या उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या पद त्याग देता है अन्यथा मन्त्री नहीं रहता या उसकी मृत्यु हो जाती है या ऋण की पूरी-पूरी राशि उस पर प्रोदभूत व्याज सहित तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगी। (सरकार उक्त पर देय की राशि को "भू-राजस्व की बकाया" के रूप में वसूल करने के लिए स्वतन्त्र होगी)।

इसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने पहल लिखे दिन और तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त श्री ने

हस्ताक्षर (नाम और पद)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

.....
(अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

1.

2.

साक्षियों के हस्ताक्षर

उधार लेने वाले का नाम और पदनाम

प्ररूप—II

मोटर यान अग्रिम के लिए बन्धक-पत्र का प्ररूप

(नियम 8 देखें)

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, समनुदेशिनी और विधिक प्रतिनिधि भी है और दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "हिमाचल प्रदेश सरकार" जिसके अन्तर्गत उसके पदोत्तरवर्ती और समनदेशिनी भी हैं) के बीच आज तारीख को किया गया है।

उधार लेने वाले ने रुपये (केवल रुपये) के लिए आवेदन किया है और हिमाचल प्रदेश मन्त्री वित्त और भत्ते अधिनियम, 2000 के अर्धान बनाए गए हिमाचल प्रदेश मन्त्री (मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2000 के नियम 3 और 4 के अनुसार मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम प्रदान किया गया है और एक शर्त जिस पर उधार लेने वाले को उक्त अग्रिम प्रदान किया गया है/था ये है/थी कि उधार लेने वाला उक्त मोटर कार को हिमाचल प्रदेश सरकार के पास उधार लेने वाले को दी गई राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में आड़मान करेगा और उधार लेने वाले ने यथापूर्वोक्त ऐसी अग्रिम राशि के पूर्ण या अंशतः भाग से मोटर कार खरीद ली है जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसूचि में निर्दिष्ट है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला हिमाचल प्रदेश सरकार को..... (रूपये)..... (रूपये) की पूर्वोक्त राशि या उसके बचे हुए असंदत्त अवशेष को इस बिलेख की तारीख तक..... (रूपये)..... (रूपये) की राशि के समान संदाय द्वारा प्रत्येक मास के प्रथम दिन को करेगा और तत्समय देय शेष राशि पर ब्याज संदत्त करेगा और बकाया संगणना उक्त नियम के अनुसार करेगा और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसा संदाय..... द्वारा उसके वेतन से उक्त नियमों में उपबंधित रीति में विधान सभा सदस्य के रूप में संदेय वेतन या भत्तों या दण्डन से या अन्यथा मासिक कटौतियों द्वारा बसूल किया जा सकेगा और उक्त करार के अनुसरण के उधार लेने वाला आगे हिमाचल प्रदेश सरकार को उक्त अग्रिम और उक्त नियमों द्वारा उस पर अपेक्षित ब्याज सहित प्रतिभूति के रूप में मोटर को समनुदेशित और अन्तर्हित करता है जिसका विवरण नीचे लिखी अनुसूची में दिशा गया है, इसमें उधार लेने वाला यह करार करता है और घोषणा करता है कि उसमें उक्त मोटर कार की पूर्ण क्रय कीमत संदत्त कर दी है और वह अब उसकी आत्यंतिक सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और उक्त अग्रिम के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार की देय धन का बकाया जितने समय तक रहता है वह उस समय तक उक्त मोटर कार को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा या न उस सम्पत्ति में या कब्जे की को विलग करेगा, सर्वथा यह करार और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन या ब्याज की कोई उक्त किश्तें उसके देय होने से दस दिन के भीतर उक्त रीति में संदत्त या बसूल नहीं की जायेगी या उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या मोटर कार को विक्रय करता या गिरवी रखता है या उसे कब्जे से अलग करता है या दिवालिया हो जाता है या उसके किसी ऋणी से समझौता या अन्य व्यवस्था करता है या उधार लेने वाले के विरुद्ध किसी डिब्री का विनिश्चय के निष्पादन में कार्यवाही करता है, तब उक्त रूप में संगणित ब्याज सहित समस्त उक्त मूलधन देय और असंदत्त हो, तुरन्त संदेय होगी।

यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें पूर्व वर्णित किसी घटना के घटित होने पर उक्त मोटर कार का अभिग्रहण कर सकेगी और उसे हिलाए या बिना हिलाए अपने कब्जे में रख सकेगी या उक्त मोटर कार को लोक नीलामी द्वारा या निजि संविदा द्वारा विक्रय कर सकेगी और क्रय राशि में से असंदत्त और यथा पूर्वोक्त संगणित देय ब्याज सहित शेष अग्रिम और उचित रूप से उपगत सभी लागतों, प्रभारी व्ययों और इसके अधीन उसके अधिकार को बनाय रखने, अभिरक्षा करने और उगाहन के लिए किए गए या उपयुक्त रूप में उपगत संदाय रखेगी और अतिशेष यदि कोई हो उधार लेने वाले उसके निष्पादक, प्रशासक या वैयक्तिक प्रतिनिधि को संदत्त करेगी।

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त कब्जा लेने वाली या उक्त मोटर कार को विक्रय करने की शक्ति, उधार लेने वाले या उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध उक्त उपशेष बकाया की देय और ब्याज या मोटर कार को बेचे जाने की दशा में राशि जिसके द्वारा शुद्ध विक्रय अग्रिम देय राशि से कम पड़ते हों, के बारे में मुकदमा चलाने के हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

उधार लेने वाला आगे यह करार करता है कि जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई धन शोध्य और बकाया रहता है उधार लेने वाला उक्त मोटर कार को अग्नि, चोरी, दुर्घटना द्वारा हानि के विरुद्ध किसी सामान्य बीमा कारबार करने वाली किसी बीमा कम्पनी/निगम के साथ बीमा करेगा और संपरीक्षा अधिकारी के समाधान के लिए यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि सामान्य बीमा कारबार करने वाली बीमा कम्पनी/निगम में जिसके साथ उक्त मोटर कार बीमाकृत है ने सूचना प्राप्त की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पालिसी में हितबद्ध है।

उधार लेने वाला और यह करार भी करता है कि उक्त मोटर कार को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं होने देगा या उस मात्रा से अधिक क्षय नहीं होने देगा जो उसके युक्तियुक्त टूट-फूट से होती हो और आगे यह कि उक्त मोटर कार को किसी हानि या दुर्घटना घटने की दशा में उधार लेने वाला तुरन्त उसकी मरम्मत करेगा और नुकसान को पूरा करेगा।

अनुसूची

मोटर कार का विवरण
 बनाने वाले का नाम
 विवरण
 सिलेंडरों की संख्या
 इंजन संख्या
 चेसिस संख्या
 लागत कीमत

इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त (उधार लेने वाले का नाम) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से उक्त श्री ने उपरलिखित दिन और वर्ष को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

उक्त उधार लेने वाले ने

- 1..... (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
- 2..... (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय),
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से श्री..... ने

- 1..... (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
- 2..... (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

(अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

प्रारूप-III

20/11/00
18/11

बीमा पालिसी में जोड़े जाने वाले खण्ड के प्रारूप

(नियम 11 देखें)

यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री..... ने जो मोटर कार का स्वामी है जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) के पास मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में आड़मान कर दिया है और यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार ऐसे धन में भी हितवद्ध है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री.....

(इस पालिसी के अधीन बीमाकृत को उक्त मोटर कार की हानियां उसका हुए नुकसान की बात जिसे हानि या नुकसान की प्रतिभूति मुरम्मत, या पूर्वकरण या प्रतिस्थापना द्वारा नहीं की गई) को संदेय होगा

और ऐसा धन सरकार को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह मोटर कार की बन्धकदार है और उनकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की वास्तविकता निगम ने पूरा और अन्तिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाय इसकी किसी बात से बीमाकर्ता के या कम्पनी के, इस पालिसी के अधीन या सम्बन्ध में अधिकार या दायित्व का अथवा इस पालिसी के किसी निबन्धन, उपबन्ध या शर्त का न तो उपान्तरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

प्रकार-IV

(नियम 12 देखिये)

भवन निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि के लिये आवेदन का प्रारूप

1. मन्त्री का नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....

2. अपेक्षित अग्रिम धनराशि, निर्दिष्ट करते हुए कि क्या.....

(I) भवन निर्माण के लिये अपेक्षित, अथवा.....

(II) बने हुए भवन के लिये अपेक्षित.....

3. वह स्थान, जहाँ बनाया जाना है, तथा यदि ऋण बने हुए भवन की खरीद के लिये अपेक्षित हों, तो भवन की लागत के उचित होने के सम्बन्ध में वास्तुविद अर्थात् आर्किटेक्ट का प्रमाण-पत्र साथे लगाया जाए।

4. किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम धनराशि ली जानी प्रस्तावित है अथवा एक मुश्त में.....

5. ऋण वापसी के लिये प्रस्तावित किस्तों की संख्या.....

6. आया कि वह प्लॉट जिस पर मन्त्री भवन निर्माण का इरादा रखते हैं, उनके स्वामित्व और कब्जे में है.....

7. प्लॉट/जमीन, जिस पर मन्त्री भवन निर्माण का इरादा रखता है, पर उसके हक का प्रमाणित सबूत.....

8. समय जब तक मन्त्री भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ करेंगे और उसके सम्पन्न होने की अवधि.....

प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं बने हुए भवन/प्लॉट जिस पर भवन बनाया जाना है, को बन्धक रखूंगा तथा बन्धक-पत्र निष्पादित और पंजीकृत करवाएगा।

(मन्त्री के हस्ताक्षर)

1. तारीख.....

2. संलग्न.....

प्ररूप-V

(नियम 16 देखिये)

भवन निर्माण अग्रिम धनराशि के लिये बन्धक का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री..... जो कि.....
 मन्वी हिमाचल प्रदेश है (जिन्हें इसमें आगे "बन्धककर्त्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ में अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक और समनुदेशिनी भी है) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय (जिन्हें इस में आगे "बन्धक ग्राहिता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, यहां संदर्भ के अनुकूल है, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिनी भी है) आज तारीख..... को किया गया।

चूंकि एतद्द्वारा स्वत्वान्तरित, हस्तांतरित और प्रगापित की जाने वाली भूमि, दाय और परिसरों जिन्हें इसमें आगे वर्णित और अभिव्यक्त किया गया है (इसमें इसक पश्चात् "उक्त दाय" कहा गया है) पर बन्धककर्त्ता का निरंकुश रूप में अभिग्रहण और कब्जा है अथवा अन्यथा रूप में उनका वह सही हकदार है।

और चूंकि बन्धककर्त्ता ने बन्धक-ग्राहिता को अपने निजी प्रयोग के लिए अपना भवन बनाने के लिये नवनिर्मित भवन खरीदने हेतु रुपये..... को अग्रिम धनराशि के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

और चूंकि हिमाचल प्रदेश के मन्त्रियों के (भवन निर्माण के लिये अग्रिम धन ऋण) नियम, 1979 जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इनके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ के अनुकूल है, वर्तमान प्रवृत्त नियम, उनका कोई संशोधन या उनमें कोई धन वर्धन भी आता है, बन्धक ग्राहिता ने बन्धककर्त्ता को..... रुपये की उक्त रकम निम्नलिखित रूप में भुगतान योग्य अग्रिम धनराशि के रूप में देने को सहमत है:—

- (क) निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये रुपये.....
- (ख) भवन को छत सहित तक पूर्ण कर लेने के..... पश्चात् रुपये।
- (ग) अथवा एक मुश्त राशि के रूप में रुपये.....

यह करार इस बात का साक्षी है कि पूर्वोक्त करार के अनुसरण में तथा बन्धक-ग्राहिता द्वारा बन्धककर्त्ता को इसमें इससे पूर्व उल्लिखित खर्चों को करने में बन्धककर्त्ता को योग्य बनाने के प्रयोजन से इस करार के निष्पादन के पश्चात् या उससे पहले प्रदत्त रुपये..... (रुपए.....) जिनको पावनी बन्धकर्त्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है (और ऐसी ओर धनराशि जो बन्धक ग्राहिता द्वारा, बन्धककर्त्ता को इस करार में आगे उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार में दी जायगी) और उस पर उक्त नियमों में निर्धारित रीति से गणित व्याज जिसकी पुनः अदायगी के लिए बन्धकर्त्ता एतद्द्वारा संश्रावित करता है, के लिए बन्धककर्त्ता यह करार करता है,

और यह करार इस बात का साक्षी है कि

पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए बन्धकर्त्ता बन्धकग्राहिता को उस सारे भूखण्ड को, जो बन्धकर्त्ता के लगभग कब्जे में है तथा जो..... जिले के..... पंजीकरण जिला के..... उप-पंजीकरण जिला के.....

म स्थित है तथा जो उत्तर में से पूर्व में से दक्षिण में से तथा पश्चिम में से परिसिमित है एवं उस पर अब बनाये गये रिहायशी मकान तथा इसके पश्चात् बनाये जाने वाले रिहायशी मकानों के साथ उक्त दाय के सभी अधिकार सुआधिकार, अनुलग्नक और उक्त भूमि के खंड पर इसके पश्चात् खड़े किये गये या बनाये गये मकानों को बन्धक ग्राही के और उसकी ओर से पूर्ण प्रयोग के लिए इसमें इसके पश्चात् निहित परन्तुक में दिये गये विमोचन के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस द्वारा स्वन्ता-तारित हस्तांतरित और प्रयोगित करता है। सर्वथा यह भी करार किया जाना है कि यदि और ज्यों ही इस करार में उल्लिखित प्रतिभूति पर दी गई उक्त अग्रिम धनराशि रुपये (और ऐसी अन्य रकमों जिनका यथा पूर्वोक्त भुगतान किया गया हो) और उक्त नियम में उपबन्धित या किसी अन्य रीति से गणित उस पर व्याज आदि वापिस किया जाता है, तब और ऐसी स्थिति में बन्धक ग्राहीता बन्धककर्ता की प्रार्थना और लागन पर बन्धककर्ता के प्रयोग और उसकी ओर से प्रयोग अथवा जैसे वह निर्देश दे, उक्त दाय को पुनः स्वात्वातरित पुनः हस्तान्तरित और पुनः प्रयोगित करेगा और इस द्वारा यह करार अथवा घोषित किया जाता है कि यदि बन्धक कर्ता इकरार को भंग करना है और यदि उक्त रकम रुपये (और कोई अन्य रकमों जिसका यथापूर्व भुगतान किया जाना हो) और उक्त नियमों के अनुसार उस पर गणित किये गये व्याज के पूरे भुगतान से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वे मन्त्री के पद पर नहीं रहते हैं तो इस प्रकार की सभी स्थितियों में बन्धक ग्राहीता के लिये यह विधि मान्य होगी कि वह उक्त दाय को या उसके किसी अंश को इकठ्ठे या आंशिक रूप से सार्वजनिक नीलामी या निजि संविदा के द्वारा संविदा को रद्द या निरस्त करने की शक्ति के सहित विक्रय और उस द्वारा होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी हुए बिना पुनः विक्रय कर सके, तथा वह ऐसे किसी विक्रय, जिसे बन्धकग्राहीता उपयुक्त समझे, को करने और उसके लिए आवश्यक सभी कार्यों तथा आश्वासनों को निष्पन्न करने में सक्षम होगा तथा एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि बन्धक ग्राहीता विक्रीन परिसरों या उसके किसी भाग से प्राप्त विक्रय आगम में से क्रेता अथवा क्रेताओं को अचूक रूप से मुक्त करेगा, तथा एतद्वारा घोषित किया जाता है कि बन्धकग्राहीता पूर्वोक्त शक्ति के अनुसरण में किये गये विक्रय से प्राप्त धनराशि को पहले न्यास के रूप में रखेगा, उसमें से सर्व-प्रथम ऐसे विक्रय पर उपगत हुए खर्चों का भुगतान करेगा, इसके पश्चात् इस करार की प्रतिभूति पर फिलहाल देय रकमों के भुगतान की ओर उस धनराशि से रकम लगायेगा और तब शेष (यदि कोई हो) बन्धककर्ता को देगा तथा एतद्वारा यह माना जाता है तथा घोषित किया जाता है कि उक्त नियमों को इस करार का अंश समझा और माना जायेगा।

बन्धककर्ता, बन्धकग्राहीता के साथ एतद्वारा यह संश्रावित करता है कि वह बन्धककर्ता, अपनी अनुभूति के चालू रहने के दौरान इस करार और उक्त दाय के सम्बन्ध में पालित और अनुष्ठित किये जाने वाले उक्त नियमों के उपबन्धों और शर्तों का पालन और अनुष्ठान करेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप बन्धककर्ता ने इस विलेख पर ऊपर लिखित तारीख को अपने हस्ताक्षर किये हैं.....

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त बन्धककर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित

(1) पहला साक्षी .

पता

व्यवसाय

(2) दूसरा साक्षी :

पता

व्यवसाय

प्रारूप-V
(नियम 16 देखिये)

भवन निर्माण अग्रिमों हेतु प्रति हस्तान्तरण-पत्र

यह अनुबन्ध विलेख दिनांक, 2000 को एक पक्षकार के रूप में राज्यपाल हिमाचल प्रदेश (जिन्हें इसके आगे "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री मन्त्री, हिमाचल प्रदेश (जिन्हें इसके आगे "बन्धककर्ता" कहा गया है) के बीच किया गया, वह उस बन्धक-पत्र के अनुबन्ध विलेख का अनुपूरक है जोकि दिनांक 2000 को एक पक्षकार के रूप में बन्धककर्ता तथा दूसरे पक्षकार के रूप में राज्यपाल के बीच किया गया था तथा जो पुस्तिका के खण्ड पृष्ठ से पर क्रम में पंजीकृत है (जिसे इसके आगे "मुद्रण अनुबन्ध विलेख" कहा गया है)।

चूंकि मुख्य अनुबन्ध विलेख के अधीन देय राशि अदा कर दी है और उक्त विलेख की प्रतिभूति का दायित्व पूर्णतया जोधित है तथा राज्यपाल बन्धककर्ता के निवेदन पर लिखित अनुबन्ध विलेख में अन्तर्विष्ट प्रतिहस्तान्तरण जैसा कि एतद् उपरान्त समाविष्ट है के निष्पादन के लिए सहमत हो गये हैं।

अब यह अनुबन्ध-विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त मुख्य अनुबन्ध विलेख के अनुसरण और वचनों के प्रतिफल में राज्यपाल एतद्द्वारा बन्धककर्ता उसके वारिस, निष्पादक, प्रबन्धक तथा समनुदेशितों को भूमि के उन सभी भागों जो में स्थित है व उत्तर में से दक्षिण में से पूर्व में से तथा पश्चिम में लगभग तक परिसीमित है तथा जिसमें उन परिसरों से अन्यथा सामूहिक रूप से उस पर बने निवास स्थान, बाह्य कार्यालय, अश्वशाला, पाकशाला आदि सम्मिलित है तथा जो मुख्य अनुबन्ध विलेख में अन्तर्विष्ट या जिनका एतद्द्वारा प्रगोषित होना अभिव्यक्त है अथवा जो कि अब मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण अथवा इसके विमोचने के अध्याधीन किसी भी प्रकार राज्यपाल में निहित उनके अधिकारों, सुविधाओं तथा अनुलग्नकों जैसा कि मुख्य अनुबन्ध विलेख में अभिव्यक्त है तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण उसी परिसर में से अथवा पर राज्यपाल के सभी संपदा अधिकार, स्वत्वधिकार, हित, सम्पत्ति, प्रभार तथा भागे जो भी कोई हो तथा उन परिवारों जो एतद्द्वारा इससे पूर्व बन्धककर्ता, उसके वारिसों, निष्पादक, प्रबन्धक तथा समनुदेशितों में तथा उसके प्रयोग के लिए स्वीकृत नियम, तथा प्रतिहस्तान्तरित है को रखने अथवा बनाये रखने के लिये तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख द्वारा रक्षित होने के लिये उस सारे धन से अथवा उपरोक्त राशि अथवा उसके किसी अंश अथवा परिसर व मुख्य अनुबन्ध विलेख से सम्बद्ध सभी कार्यों, वादों, लेखों, दावों, भागों से सदा के लिए मुक्त करता है।

राज्यपाल एतद्द्वारा बन्धककर्ता, उसके वारिसों, समनुदेशितों तथा प्रबन्धकों के साथ इसे व्यवहृत करते हैं तथा अभिहस्ताक्षर करने हैं कि राज्यपाल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है अथवा इसके लिए जानबूझकर समनुज्ञा नहीं की है अथवा इसके लिये वह एक पक्ष अथवा सहभोगी नहीं रहे हैं जिसके द्वारा उपरोक्त परिसर अथवा उसके किसी भाग के लिए उन पर महाभियोग लाया जाए या लाया जा सकता है या स्वत्वधिकार सम्पदा अथवा इसके अन्यथा जो भी हो में परिबन्धन अथवा रुकावट लाये या लाई जा सके। इसके साक्ष्य स्वरूप इससे सम्बन्ध पक्षकारों से इस पर पहले ऊपरलिखित दिन और वर्ष की मोहर सहित अपने हस्ताक्षर किए हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल की ओर से के सम्मुख हस्ताक्षरित मोहर बन्द तथा प्रदत्त।

निम्नलिखित की उपस्थिति में :

[Authoritative English Text of the Department Notification No. GAD-C (PA) 4-1/95-II, dated 31-10-2000 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st October, 2000

No. GAD-C (PA) 4-1/95-II.—In exercise of the powers conferred by section 15 read with sections 8 and 9 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to regulate Advance for Motor Car and House Building of the Ministers, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Definition.*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

- (a) "Act" means the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.
- (b) "Audit Officer" means the "Accountant General, Himachal Pradesh.
- (c) "Form" means Form appended to these rules.
- (d) "Sanctioning Authority" means the Governor of Himachal Pradesh.
- (e) Terms and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Motor Car advance :

3. *Advance when admissible.*—A Minister may be paid an advance for the purchase of a motor car in order that he may be able to discharge conveniently and efficiently the duties of his office subject to the conditions hereinafter specified.

4. *Maximum amount of advance.*—The maximum amount which may be advanced to a Minister for the purchase of a motor car shall not exceed rupees ten lacs or the actual price of the motor car which is intended to be purchased, whichever is less :

Provided that in case the Minister has taken the house building advance under rule 13 of these rules or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance of Loan for House Building) Rules, 1979, then the total amount of the motor car advance together with the house building advance already availed of by the Minister shall not exceed the limit of ten lacs rupees :

Provided further that where a Minister has taken the motor car advance in his capacity as the Speaker or the Deputy Speaker or the Member of Legislative Assembly, as the case may be, the total amount of motor car advance together with the motor car advance already given to him shall not exceed the limit of ten lacs rupees.

5. *Recovery of advance.*—(1) Recovery of the advance granted under rule 4 of these rules together with interest thereon, shall be made in 180 equal monthly instalments. The Government may order recovery to be made in a smaller number of instalments keeping in view the remaining period of term of office or if the Minister himself so desires. The deduction shall commence with the first issue of salary after the advance is drawn.

(2) Simple interest at the rate of 5% per annum shall be charged in respect of the loans sanctioned on or after 3-12-1993 :

Provided that the rate of interest fixed on the loans sanctioned prior to 3-12-1993 shall hold good for the entire duration of the advance.

(3) If a Minister ceases to be a Minister for any reason before the advance is fully repaid, but continuous to be the Member of Legislative Assembly the monthly instalments shall be recovered by the Vidhan Sabha Secretariat out of the various allowances admissible to him as a Member of the Legislative Assembly.

(4) If a Minister also ceases to be the Member of the Legislative Assembly, before the advance is fully repaid, but he is entitled to draw pension, the recovery shall be made by the Vidhan Sabha Secretariat out of the pension payable to him and the balance amount of the monthly instalments shall be deposited by him regularly in the Government Treasury and in token of proof of such payment, he shall submit a copy of the challan to the Government regularly.

(5) In case he ceases to be a Member of Legislative Assembly and is also not entitled to draw the pension, the monthly instalments, together with interest accrued thereon shall be deposited by him regularly in Government Treasury and he shall submit a copy of the Challan to the Government in token of having deposited the amount.

(6) In the event of death before the recovery of advance alongwith interest thereon, the legal heir/heirs of Minister or M. L. A., shall deposit the balance of the amount of the loan and interest accrued thereon in lump-sum in the Government treasury and submit a copy of the Challan to the Government in token of having deposited the whole amount.

(7) If the Minister or his legal representative(s), as the case may be, make(s) default in regular payment of instalments either of the principal or interest thereon, or if he (they) become(s) insolvent(s) or he (they) fail(s) to observe or perform the terms and conditions of the loan, then in such a case the whole of the principal amount of the loan or so much thereof as shall then remain due and unpaid, shall become payable forthwith in lump-sum to the Government with interest thereon at the rate specified in sub-rule (2).

The Government shall be at liberty to recover the said outstanding amount as "Arrears of Land Revenue". The recovery to be effected by Vidhan Sabha Secretariat, as envisaged in the above conditions, will be regulated under the Himachal Pradesh Legislative Members (Advance of Loan for purchase of Motor Car) Rules, 1979, as in force from time to time.

Explanation.—The amount of the advance to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees except in the case of last instalment when the remaining balance including any fraction of a rupee shall be recovered.

6. *Sale of motor car.*—(1) Except when a Minister relinquishes his office, the office, the previous sanction of the Government shall be obtained for the sale by the Minister of the motor car purchased with the aid of an advance, if such advance together with the interest accrued thereon has not been fully repaid. If a Minister wishes to transfer the motor car and the liability attaching thereto to another Minister, he may be permitted to do so under the orders of

the Government, subject to furnishing of a declaration that he is aware that the motor car transferred to him remains subject to mortgage to the Government and that he is bound by the terms and provisions of the Mortgage Bond, executed under rule 8 by the Minister who transferred the car.

(2) In all cases where a motor car is sold before the advance with interest thereon has been fully repaid, the sale proceeds must be applied, so far as may be necessary towards the repayment of such outstanding balance:

Provided that when the motor car is sold only in order that another motor car may be purchased, the Government may permit the Minister to apply the sale proceeds towards such purchase, subject to the following conditions, namely:—

- (a) the amount outstanding shall not be permitted to exceed the cost of the new car;
- (b) the amount outstanding shall continue to be repaid at the rate previously fixed; and
- (c) the new car shall be mortgaged to the Government and also insured.

7. *Period within which negotiations for purchase of car, may be completed.*—A Minister who draws an advance for the purchase of a motor car shall complete negotiations for the purchase of and make final payment for the motor car within one month which he draws the advance failing such completion and payment, the full amount of the advance drawn with interest thereon for one month shall be refunded to the Government. The period of one month for completion of the deal may, however be extended by the Government in individual cases. An advance will not be admissible when a motor car has already been purchased and paid for in full.—In a case in which payment has been made in part, the amount of advance will be limited to the balance to be paid as certified by the Minister.

8. *Execution of agreement.*—At the time of drawing the advance the Minister shall execute an agreement in Form-I and on completing the purchase, he shall further execute a mortgage bond in Form II hypothecating the motor car to the Government as security for the advance. The cost price of the motor car shall be entered in the Schedule of specifications attached to the mortgage bond.

Note.—The agreement forms shall be executed on plain paper and stamp duty/registration charges, if any, on the instrument, shall be borne by the State Government.

9. *Certificate to the Audit Officer.*—When an advance is drawn, the sanctioning authority shall furnish to the Audit Officer a certificate that the agreement in Form II has been signed by the Minister drawing the advance and that it has been found to be in order. The sanctioning authority shall see that the motor car is purchased within one month from the date on which the advance is drawn such period as may have been specifically allowed in individual cases by the Government for completion of the deal under rule 7 and shall submit every mortgage bond promptly to the Audit Officer for examination before final record.

10. *Safe custody and cancellation of mortgage bond.*—The mortgage bond shall be kept in the safe custody by the sanctioning authority. When the advance together with the interest thereon has been fully repaid the bond shall be returned to the Minister concerned duly cancelled after obtaining a certificate from the Audit Officer as to the complete repayment of the advance and interest.

11. *Insurance of the Motor Car.*—The motor car purchased with the advance shall be insured against full loss by fire, theft or accident with the any Insurance Company/Corporation transacting General Insurance Business. The insurance policy shall contain a clause as in Form III by

which the Corporation agrees to pay to Government instead of the owner any sums payable in respect of loss or damage to the motor car which is not made good by repair, re-instatement or replacement such insurance should be effected within one month of the date of the purchase.

12. Advance when admissible.—On an application made in Form IV, a Minister, may be paid a repayable advance, for the construction of his own house or for the purchase of a built-up house with a view to have a reasonable standard of living.

13. Maximum amount of advance.—The maximum amount which may be advanced to a Minister for the construction of a house or for the purchase of a built up house shall not exceed ten lacs rupees or the actual price or cost of the construction of house whichever is less:

Provided that case the Minister has taken the motor car advance under rule 4 of these rules or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance of Loan for purchase of Motor Car) Rules, 1979, then the total amount of house building advance together with the motor car advance already availed of by the Minister, shall not exceed the limit of ten lacs rupees.

Provided further also that where a Minister has taken the house building advance in his capacity as the Speaker or the Deputy Speaker or the Member of Legislative Assembly, as the case may be, the total amount of house building advance together with the house building advance already to him shall not exceed the limit of ten lacs rupees.

14. Mode of payment.—The amount of advance admissible under these rules shall be paid in the following manner:—

(1) For the construction of his own house:—

- (a) first instalment equal to 50% of the advance sanctioned, for starting the construction; and
- (b) second and final instalment of remaining 50% of the total advance, after the house has been completed upto the roof level.

(2) For the purchase of the built-up house—in lump-sum.

Note.—A certificate which must be furnished by the Minister certifying that the amount drawn has been utilised by him for the purpose for which it was advanced to him will be sufficient proof of the amount having been actually utilised by him for the aforesaid purpose.

15. Recovery of advance.—(1) Recovery of the advance granted under rule 13 of these rules together with interest thereon, shall be made in 180 equal monthly instalments. The Government may order recovery to be made in a small number of instalments keeping in view the remaining period of term of office or if the Minister himself so desires. The deduction shall commence with the first issue of salary after the first instalment of or lump sum advance is drawn.

(2) Simple interest at the rate of 5% per annum shall be charged in respect of the loans sanctioned on or after 3-12-1993 :

Provided that the rate of interest fixed on the loans sanctioned prior to 3-12-1993 shall hold good for the entire duration of the advance.

(3) If a Minister ceases to be a Minister for any reason, before the advance is fully repaid, but continuous to be Member of Legislative Assembly, the monthly instalments shall

be recovered by the Vidhan Sabha Secretariat out of the various allowances admissible to him as Member of Legislative Assembly.

(4) If a Minister also ceases to be the Member of Legislative assembly before the advance is fully repaid, but he is entitled to draw pension, the recovery shall be made by the Vidhan Sabha Secretariat out of the pension payable to him and the balance amount of the monthly instalments shall be deposited by him regularly in the Government Treasury and in token of proof of such payment he shall submit a copy of the challan to the Government regularly.

(5) In case he ceases to be a Member of Legislative Assembly and is also not entitled to draw the pension, the monthly instalments, together with interest accrued thereon, shall be deposited by him regularly in Government Treasury and he shall submit a copy of the challan to the Government in token of having deposited the amount.

(6) In the event of death before the recovery of advance alongwith interest thereon, the legal heir/heirs of the Minister or M.L.A. shall regularly deposit the monthly instalments in the Government Treasury and submit the copy of the challan to the Government, every month in token of having deposited the amount.

(7) If the Minister or his legal representatives, as the case may be makes default in the regular payment of instalments either of the principal or interest thereon or if he becomes insolvent or he fails to observe or perform the terms and conditions of the loan, then in such a case the whole of the principal amount of the loan or so much thereof as shall then remain due and unpaid shall become payable forthwith in a lump sum to the Government with interest thereon at the rate specified in sub-rule (2). The Government shall be at liberty to recover the said outstanding amount as "Arrears of Land Revenue".

Explanation.—The amount of the advance to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees except in the case of last instalment when the remaining balance including any fraction of a rupees shall be recovered.

16. Liability to execute mortgage deed securing the payment of the loan.—In order to secure Government from loss consequent on the demise of a Minister or his ceasing to be a Minister, before full repayment of the advance and the interest accrued thereon the house so built-up or purchased, together with the land on which it stands upon, shall be mortgaged to the Himachal Pradesh Government in Form-V which shall be executed before the payment of the first instalment or of lump sum, as the case may be, as made, and on full payment of the amount which accrued to be due the mortgage shall be released after the execution of the reconveyance deed in Form-VI. On the execution of the mortgage deed, the sanctioning authority shall satisfy itself as to the correctness of the applicant's title to the land upon which the house stands or is proposed to be built.

17. Liability to keep premises in good repairs and insure the premises against fire risks, etc.—The Minister shall maintain the house in good repair at his own cost and shall also keep it free from all encumbrances. He shall also have it insured for a sum not less than the amount of advance sanctioned, against fire, flood etc., and furnish an annual certificate to this effect.

18. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971. The Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971. The Himachal Pradesh Ministers (Advance of loan for House Building) Rules, 1981 and the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of loan for House Building) Rules, 1982 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been taken or done under these rules.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

FORM-I

FORM OF AGREEMENT TO BE EXECUTED AT THE TIME OF DRAWING AN ADVANCE FOR THE PURCHASE OF MOTOR CAR

(See rule 8)

An agreement made this day of between Shri Minister of Himachal Pradesh (hereinafter called the "Borrower" which expression shall include his heirs, administrators, executors, legal representatives and assigns) of the one part and the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter called "the Government of Himachal Pradesh" which expression shall include his successors and assigns) of the other part.

Whereas the Borrower has under the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2000 applied to the Government for a loan of Rs. (Rupees.) for the purchase of a motor car and the Government has agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained.

2. Now it is hereby agreed between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs. (Rupees. only) paid by the Government of Himachal Pradesh to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges with the Government—

(1) to pay the Government that said amount with interest calculated according to the said rules by 180 monthly deductions from his salary or allowances pension payable as M.L.A. (as much as could be recovered and the rest to be deposited in cash by him in Government Treasury) as provided for by the said rules and hereby authorises the Government to make such deductions and in case the Borrower is not entitled to draw the pension, the monthly instalments together with interest accrued thereon, shall be deposited by him regularly in Government treasury and he shall submit a copy of the challan to the Government in token of having deposited the amount as provided for by the said rules :

(2) within one month from the date of these presents to expend the full amount of the said loan in the purchase of a motor car or if the actual price paid is less than the loan, to repay the difference to the Government forthwith ; and

(3) to execute a document hypothecating the said motor car to the Government as security for the amount lent to the borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said rules.

And it is hereby lastly agreed and declared that if the motor car is not purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or within the extended period or if the Borrower within that period becomes insolvent or relinquishes his office or otherwise ceases to be Minister or dies, the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediately become due and payable.

(The Government shall be at liberty to recover the said outstanding amount as "Arrears of Land Revenue").

In witness whereof the Borrower has hereunto set his hand the day and year first before written.

Signed by the said Shri-----

In the presence of.....

Signed by (Name and designation).....

For and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of

(Signature and designation of the Officer).

1.

2.

(Signature of Witnesses).

Name and designation of the Borrower

FORM-II

FORM OF MORTGAGE BOND FOR MOTOR VEHICLE ADVANCE

(See rule 8)

This indenture made this..... day of..... between..... (hereinafter called "borrower" which expression shall include his heirs, administrators, executors, assigns and legal representatives) of the one part and the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter called the "Government of Himachal Pradesh" which expression shall include his successors and assigns) of the other part ;

Whereas the Borrower has applied for and has been granted an advance of Rs.... (Rupees.....) only to purchase a motor car in the terms of rules 3 and 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2000 made under the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (hereinafter referred to as "the said Rules") and whereas on of the condition upon which the said advance has been/was granted to the Borrower is/was that the Borrower will/would hypothecate the said motor car to the Government of Himachal Pradesh as security for the amount lent to the Borrower and whereas the

borrower has purchased with whole or partly with the amount so advanced as aforesaid the motor car particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written :

Now, this indenture witnesseth that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to pay to the Government of Himachal Pradesh the sum of Rs.....(Rupees.....) aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by equal payment of Rs.....(Rupees.....) each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing calculated according to the said rules and the Borrower doth agree that such payments may be recovered by..... monthly deductions from his salary (Allowances or pension payable as M.L.A. or otherwise) in the manner provided by the said rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth hereby assign and transfer unto the Government of Himachal Pradesh the motor car the particulars whereof are set out in the Schedule..... hereunder written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said rules :

And the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full the purchase price of the said motor car and that the same is his absolute property and that he has not pledged and so long as any money remains payable to the Government of Himachal Pradesh in respect of the said advance, will not sell, pledge or part with the property in or possession of the said motor car :

Provided always and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of principal or interest shall not be paid or recovered in the manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said motor car or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgement against the Borrower, the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid together with interest thereon calculated as aforesaid shall forthwith become payable ;

And it is hereby agreed and declared that the Government of Himachal Pradesh may on the happening of any of the events herein before mentioned seize and take possession of the said motor car and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said motor car either by public auction or private contract and may, out of the sale money retain the balance of the said advance then remaining unpaid and any interest due thereon calculated as aforesaid and all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realising his rights thereunder and shall pay over the surplus, if any, to the Borrower, his executors, administrator or personal representatives :

Provided further that the aforesaid power of taking possession or selling of the said motor car shall not prejudice the right of the Government of Himachal Pradesh, to sue the Borrower or his legal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of the motor car being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing :

And the Borrower hereby further agrees that so long as any money are remaining due and owing to the Government of Himachal Pradesh, he the Borrower will ensure and keep insured the said motor car against loss or damage by fire, theft or accident with any Insurance Company/Corporation transacting any General Insurance Business and will produce evidence to the satisfaction of the Audit Officer that the Insurance Company/Corporation transacting any General Insurance Business with whom the said motor car is insured have received notice that the Government of Himachal Pradesh is interested in the policy.

And the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said motor car to be destroyed or injured or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof and further, that in the event of any damage or accident happening to the said motor car the Borrower will forthwith have the same repaired and made good.

THE SCHEDULE

Description of motor car
Maker's name
Description
Number of cylinders
Engine number
Chassis number
Cost price

In witness where of the said(Borrower's name) and said Shri.....for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh have hereinto set their respective hands the day and year first above written.

Signed by the said in the presence of :

1.
2.
(Signature of witnesses)

(Signature and designation of the Borrower)

(Signed by name and designation)

.....

for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of :—

1.
2.
(Signature of witnesses)

(Signature and designation of the Officer.)

FORM-III

FORM OF THE CLAUSE TO BE INSERTED IN INSURANCE POLICIES

(See Rule 11)

It is hereby declared and agreed that Shri.....(the owner of the motor car hereinafter referred to as the insured in the Schedule of this policy) has hypothecated the car to the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter called the "Government") as security for advance for the purchase of motor car and it is further declared and agreed that the said Government is interested in moneys which but for this endorsement would be payable to the said Shri.....(the insured under this policy) in respect of the loss or damage to the said motor car (which loss or damage is not made good by repair, reinstatement or replacement) and such moneys shall be paid to the Government as long as they are the mortgages of the

motor car and their receipt shall be full and final discharge to the company in respect of such loss or damage.

2. Save as by this endorsement expressly agreed nothing shall modify or effect the rights or liabilities of the insured or the company respectively under or in connection with this policy or any term, provision or condition thereof.

FORM-IV

(See rule 12)

APPLICATION FORM FOR HOUSE BUILDING ADVANCE

1. Name of the Minister in (in block letters).....
2. Amount of advance required indicating whether:—
 - (i) required for construction of a house or
 - (ii) for the purchase of a built-up house.
3. Place where the house is proposed to be constructed and if the loan is required for the purchase of built up house a certificate from the architect with regard to the reasonableness of the cost of the house be attached.
4. Number of instalments in which the advance is proposed to be drawn or in lump-sum.
5. Number of instalments in which the advance is proposed to be repaid.
6. Whether the plot on which the Minister intends to construct the house is in his proprietorship and possession.
7. Authentic proof of his title to the plot land on which the Minister intends to construct the house.
8. Time by which the Minister propose to undertake the construction of the house and completion.

Certified that the above information is correct to the best of my knowledge and that I undertake to mortgage the built-up house the plot on which the house is to be constructed and execute and register a mortgage deed.

Dated.....

(Signature of the Minister)

Enclose :

FROM-V

(See rule 16)

FORM OF MORTGAGE FOR HOUSE BUILDING ADVANCE

This INDENTURE is made the day of between Himachal Pradesh (hereinafter referred to as "the mortgagor" which term shall where the context so admits include his heirs, executors administrators assigns and legal representative (s) of the one part and the Governor of the Himachal Pradesh (hereinafter referred to as "the mortgagee" which term shall where the context so admits include his successors and assigns) of the other part :

WHEREAS the mortgagor is absolutely seized and possess of or other wisewell entitled to the land hereditament and premises hereinafter described and expressed to be hereby conveyed transferred and assured (hereinafter referred to as "the said hereiditaments").

AND WHEREAS THE MORTGAGOR HAS APPLIED TO THE MORTGAGEE for an advance of the sum of Rs.....(Rupees.....) for the purpose of enabling him to construct his own house purchase a new built-up house for his own personal use :

AND WHEREAS under the provision contained in the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2000, (hereinafter referred to as "the said rules" which expression shall where the context so admits include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force) the mortgagee has agreed to advance to the mortgagor the said sum of Rs.(Rupees.....)only, payable as follows :

- (a) Rs.....for starting construction.
- (b) Rs.....after the house has been completed.....upto roof level.
- (c) in lump sum.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs.....(Rupees.....) paid on or before the execution of these presents to the mortgagor by the mortgagee (the receipt whereof the mortgagor doth hereby acknowledge for the purpose of enabling the mortgagor to defray the hereinbefore receipt expenses the mortgagor hereby convenants with the mortgagee to repay to the mortgagee the said sum of Rs.....(Rupees.....) (and such further sum as shall hereafter be paid by him to the mortgagor pursuant to the hereinafter rected agreement in that behalf).

AND THIS INDENTURE ALSO WITNESSETH that for the consideration afore-said the mortgagor doth hereby convey, transfer and assure unto the mortgagee all that piece of land situated in thedistrict of.....registration District of.....sub-registration District of.....containing.....more or less now in the occupation of the mortgagor and bounded on the East by.....on the North by.....on the South by.....and on the West by.....together with the dwelling house now erected or hereafter to be rerected on the said piece of land together with all rights easements and appurtenances to the said hereditaments and buildings hereafter erected and built on the said piece of land unto and to the use of the mortgagee absolutely subject to the proviso for redemption hereinafter contained.

PROVIDED ALWAYS if and as soon as the said advance of Rupees (and of such further sums as may have been paid as aforesaid) made upon the security of these presents shall have been repaid and interest thereon calculated according to the said rules as in the said rules mentioned or by any other means whatsoever then and in such case the mortgagee will upon the request and at the cost of the mortgagor reconvey, retransfer or reassure the said hereditaments until and to the use of the mortgagor or as he may direct and it is hereby agreed and declared that it there shall be any breach by the mortgagor of the covenants on his part herein contained or if he dies or ceases to be a Minister before the said sum of Rupees.....(and any further sum as may have been paid as aforesaid) and interest [thereon calculated according to the said rules shall have been fully paid off then and in any of such cases it shall be lawful for the mortgagee to

sell the said hereditaments or any part thereof either together or in partial and either by public auction or by private contract with power to nullify or rescind any contract for sale and to resell without being responsible for any loss which may be occasioned thereby :

AND to do and execute all such acts and assurances for effectuating any such sale as the mortgagee shall think fit and it is hereby declared that the receipt of the mortgagee for the purchase money of the premises sold or any part thereof shall effectually discharge the purchaser or purchasers therefrom AND it is hereby declared that the mortgagee shall hold the moneys to arise from any sale in pursuance of the aforesaid power UPON TRUST in the first place thereout to pay all expenses incurred on such sale and in the next place to apply such moneys in or towards satisfactions of the moneys for the time being owing on the security of these presents and then to pay the surplus (if any) to the mortgagor AND it is hereby agreed and declared that the said rules shall be deemed and taken to be part of these presents.

The mortgagor hereby covenants with the mortgagee that he, the mortgagor, will during the continuance of his security observe and perform all the provisions and conditions of the said rules on his part to be observed and performed in respect of these presents and the said hereditaments.

IN WITNESS whereof the mortgagor, hath hereunto set his hand the day and year first above written.

Signed by the said (Mortgagor) .

In the presence of:
1st witness :

Address :

Occupation :

2nd Witness :

Address :

Occupation :

FORM-VI

(See rule 16)

RECONVEYANCE FOR HOUSE BUILDING ADVANCES

THIS INDENTURE is made the day of BETWEEN THE GOVERNOR OF HIMACHAL PRADESH (hereinafter called the Government) of the one part and Shri. a Minister of the Himachal Pradesh (hereinafter called "the mortgagor") of the other is supplemental to an indenture of mortgage, dated the day of and made BETWEEN THE MORTGAGOR OF THE one part and the Governor of the other part and registered at in Book Volume pages to and as No. for hereinafter called the PRINCIPAL INDENTURE.

WHEREAS all moneys due and owing on the security of the PRINCIPAL INDENTURE have been fully paid and satisfied and the Governor has accordingly at the request

of the mortgagor agreed to execute such reconveyance of the mortgaged premises in the within written INDENTURE comprised as is hereinafter contained.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the premises, the Governor doth hereby grant, assign and reconvey upto the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns ALL THAT piece of land situated in the containing.....more or less bounded on the North by.....on the South by.....on the East by.....on the West by.....to therewith the dwelling house and out offices, stables cook-rooms and out buildings thereon AND ALL and singular other than premises in the PRINCIPAL INDENTURE comprised or expressed to be thereby assured or which now are by any means vested in the Governor subject to redemption under or by virtue of the PRINCIPAL INDENTURE with their rights, easements and appurtenances as in the PRINCIPAL INDENTURE expressed and all the estates right, title, interest property clean and demand whatsoever of the Governor into out of or upon the same premises by virtue of the PRINCIPAL INDENTURE to have and to hold the premises hereinbefore expressed to be hereby granted, assigned and reconveyed unto and to the use of the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns forever freed and discharged from all moneys intended to be secured by the PRINCIPAL INDENTURE and from all actions, suits, accounts, claims and demands for, or in respect of the said moneys or any part thereof or PRINCIPAL INDENTURE of anything relating to the premises.

AND the Governor hereby covenants with the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns that the Governor has not done or knowingly suffered or been party or privy to anything whereby the said premises or any part thereof, are, is or can be impeached, encumbered or affected in title, estate or otherwise however IN WITNESS whereof the parties hereto have hereunto set their hands and seals the day and year first above written.

Signed, sealed and delivered by for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh.

In the presence of :

